मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। शर्मा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली गए थे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल ईंजन सरकार दिल्ली के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। समारोह में शामिल हुईं दीया कुमारी ने कहा, भाजपा सरकार दिल्ली में सुशासन के नए मानक स्थापित करेगी, दिल्ली को स्वच्छ व सुंदर बनाएगी।

दिल्ली में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व 6 मंत्रियों ने शपथ ली

शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया गया

- **शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सहित कई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री मौजूद थे।**
- **विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व एन.डी.ए. घटक दलों के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।**

नयी दिल्ली, 20 फरवरी। छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आयीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुरानी कार्यकर्ता रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की बागडोर संभाली। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने गुप्ता और उनके सहयोगी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। गुप्ता शालीमार बाग से भाजपा की विधायक चुनी गयी हैं।

गुप्ता के बाद क्रमश: नयी दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर विधायक बने प्रवेश साहिब सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली।

रामलीला मैदान में तीन मंच सजे थे। बांये मंच पर विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु और कई प्रमुख संत विराजमान थे। बीच के मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने की व्यवस्था की गयी थी और इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मोदी मंत्रिमंडल में शामिल अन्य मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ये तीसरे नं. पर भाजपा और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उपस्थित थे।

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्र गान से हुयी। इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना को पढ़ा, जिसमें रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री और अन्य छह विधायकों को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से अनुमति दी गयी थी।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई। वे जमीनी स्तर से उठकर आई हैं, कैंपस राजनीति, प्रदेश संगठन, नगर निगम प्रशासन में सक्रिय रहीं और अब विधायक तथा मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। उन्हें सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।

शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री व उनके 6 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया।

मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने सामान्य प्रशासन, सेवाएं, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन, जनसंपर्क, सतर्कता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखे हैं।

प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, गुरुद्वारा चुनाव, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल, जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र सिंह इंद्राज समाज कल्याण, एससी और एसटी कल्याण, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, डवलपमेंट, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली। डॉ. पंकज कुमार सिंह- स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। पंकज सिंह खुद पेशे से डॉक्टर हैं।

दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज से पहले यह सीएम कार्यालय मीडिया के लिए नहीं खुला था। आज से यह सभी के लिए खुला रहेगा। सभी का स्वागत है।

उन्होंने कहा कि आज शपथग्रहण समारोह के बाद हमने सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभाल लिया है। शाम सात बजे कैबिनेट पहली बैठक बुलाई गई है। इससे पहले शाम पांच बजे यमुना घाट पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन व्यर्थ नहीं होगा। एक-एक वादे पूरे किए जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में रोहिणी से चौथी बार जीते वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है।

ऑनलाइन अश्लील कंटैंट व सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए बिल लाएगी सरकार

नई दिल्ली, 20 फरवरी। रणवीर अलाहबादिया पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना के शो "इंडियाज़ गॉट टैलेंट" में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसे लेकर देश में अलग-अलग जगहों पर एफआईआर हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री को लेकर जवाब मांगा है। सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया बिल पर काम को तेज कर दिया है।

सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। इस नए कानून में यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे। ज्ञातव्य है कि इस बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है।

- **रणवीर अलाहबादिया के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और ऑनलाइन अश्लील कंटैंट नियंत्रित करने के बारे में सरकार से जवाब मांगा है।**

रणवीर अलाहबादिया के केस के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है।

दिल्ली में भाजपा ने बुलाई एनडीए की बैठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने बैठक में सहयोगी दलों के साथ भावी रणनीति पर चर्चा की

- **मीटिंग में तेलुगदेशम के मुखिया व आंध्र के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू, जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा व केन्द्रीय मंत्री लल्लन सिंह शामिल हुए।**
- **मीटिंग में भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रमुख थे।**

नयी दिल्ली, 20 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा सरकार के गठन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन किया और इस कड़ी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के नेताओं के लिए भोज का आयोजन किया गया, जिसमें शासन की रणनीतियों, नीति समन्वय और राजग शासित राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गयी।

इंपीरियल होटल में आयोजित इस भोज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए।इस बैठक को आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा इससे पहले भी सरकारों के गठन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए शपथ ग्रहण समारोहों में भी राजग के तमाम नेता जुटे थे। अब दिल्ली में भी इसी तरह का राजनीतिक संदेश देने के लिए यह हाई-प्रोफाइल मीटिंग रखी गयी जिसमें राजग के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में अमित शाह, जे.पी. नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस बैठक में शामिल हुए।

घटक दलों ने भी मीटिंग में भाग लिया। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल हुए। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी बैठक का शिरकत की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भोज में शामिल होने वाले राजग के नेताओं ने शासन की रणनीतियों, नीति समन्वय और राजग शासित राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की।

सेना के लिए 1868 रफ टैरेन ट्रक खरीद को मंजूरी

नयी दिल्ली, 20 फरवरी। रक्षा मंत्रालय ने सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 697.35 करोड़ रुपये की लागत से 1868 रफ टैरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक की खरीद के लिए एसीई लिमिटेड और जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरूवार को बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये। रफ टैरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका इस्तेमाल सेनाओं में भारी मात्रा में रसद व सैन्य सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इससे सेना, वायुसेना और नौसेना की परिचालन प्रभावशीलता बढ़ेगी। यह खरीद देश से ही होने के कारण इससे राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण बढ़ेगा। इस परियोजना में घटकों के उत्पादन के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। यह खरीद भारत के रक्षा बुनियादी ढ ांचे के आधुनिकीकरण और स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **इस पर 697.35 करोड़ रूपए की लागत आएगी।**

नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन के लिए रेल डिविजन ने नए नियम घोषित किए

- **8 से 16 नम्बर तक के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आगमन के लिए आर.पी.एफ. से अनुमति लेनी होगी।**
- **नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ के बाद यह फैसला लिया गया है।**

नई दिल्ली, 20 फरवरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर आठ से 16 तक किसी भी ट्रेन के आगमन से पहले अधिकारियों को अब आरपीएफ से परमिशन लेना होगा। दिल्ली रेल डिविजन ने गुरुवार को इस नए नियम की घोषणा की। यह फैसला 15 फरवरी को प्लेटफॉर्म संख्या 14 के पास सीढ़ी पर हुई भगदड़ जैसी घटना न हो सके, इसके लिए लिया गया है। आम तौर पर आठ से 16 तक के प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज, पटना, कानपुर, लखनऊ, हावड़ा आदि पूर्वी क्षेत्रों से आने वाली या वहां से जाने वाली सभी ट्रेन ठहरती हैं तथा महाकुंभ के कारण इन सभी ट्रेन में यात्रियों की बहुत भीड़ होती है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली डिविजन की तरफ से 19 फरवरी को जारी किए गए एक सर्कुलर में स्टेशन अधिकारियों को एक नई प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत आरपीएफ से मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन को इच्छित प्लेटफॉर्म, यानी संख्या आठ से 16 पर ठहराया जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक, स्टेशन अधिकारी पावर केबिन के आरपीएफ कर्मियों को ट्रेन के आगमन के बारे में 15 मिनट पहले सूचना देंगे और उन्हें उस प्लेटफॉर्म नंबर की भी जानकारी देंगे, जिस पर ट्रेन पहुंचने वाली है। आरपीएफ कर्मचारी स्टेशन और जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचने वाली है, वहां भीड़ की स्थिति के बारे में सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष और फुट ओवर ब्रिज/प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ कर्मियों के साथ को-ऑर्डिनेट करेंगे, फिर, मंजूरी मिलने के बाद, पावर केबिन के आरपीएफ कर्मी इच्छित प्लेटफॉर्म पर विशेष ट्रेन को ठहराने/आगमन की मंजूरी देंगे।

'संगम के जल पर केन्द्र व राज्य सरकार के आंकड़े विरोधाभासी'

लखनऊ, 20 फरवरी। महाकुंभ के दौरान संगम के जल में प्रदूषण की मात्रा पर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संगम के जल को लेकर आंकड़े अलग-अलग हैं।

- **सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अब देखना है कि क्या यूपी सरकार केन्द्र सरकार के संगम जल प्रदूषण के आंकड़े को स्वीकार करेगी या उसे सनातन विरोधी करार देगी।**

उन्होने कहा कि दिल्ली वालों के आंकड़े यूपी वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब देखना है यूपी का नया डेटा दिल्ली स्वीकार करती है या नहीं। यूपी सरकार दिल्ली वालों के आंकड़ों को नहीं मान रही है।

अखिलेश ने कहा केन्द्र सरकार कह रही है कि संगम का पानी स्नान करने लायक नहीं है, तो मान कर चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सनातनी नहीं मानेंगे। अब क्या लखनऊ वाले कहेंगे कि दिल्ली वाले सनातनी नहीं है। मैं तो मांग करूंगा कि भाजपा के नेताओं के घर संगम का पानी टंकी भर कर पहुंचाया जाय।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले सदन में जवाब नहीं दिया। जिसके चलते राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष का संबोधन नहीं हो सका।

नेता प्रतिपक्ष की बात पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई तो विपक्ष के सदस्य भी खड़े होकर बोलने लगे। दोनों पक्षों में नोक-झोंक के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बीच-बचाव किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने एक मंत्री द्वारा सदन में तख्ती लेकर आने पर आपत्ति जताई तो फिर हंगामा होने लगा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

यूक्रेन युद्ध का "अन्त" क्या कोरिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता कर सकता है और पुतिन को भविष्य में आक्रामकता के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि कोरिया स्टाइल का "फ्रोज़न कान्फ्लिक्ट" यथार्थवादी परिणाम हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अधिक रियायतों की आवश्यकता नहीं होती। कोरिया शैली का "फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट" एक लंबा सैन्य गतिरोध होता है, जहां बड़े पैमाने पर सक्रिय युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन कोई औपचारिक शांति संधि नहीं होती है, जिससे स्थिति अनसुलझी रहती है और समय-समय पर तनाव पैदा होता रहता है। यह शब्द कोरिया युद्ध (1950-1953) के बाद की कोरिया प्रायद्वीप की स्थिति से लिया गया है। जहाँ, युद्धविराम से युद्ध की समप्ति हुई, लेकिन, किसी औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। जिसका मतलब है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से अब भी युद्धरत हैं।

इस तरह की स्थिति कैसी होगी? यह कुछ इस तरह हो सकती है।

प्रथम, यूक्रेन और रूस एक दीर्घकालिक युद्धिविराम पर सहमत होते हैं, जिसमें रूसी-आधिकारिक क्षेत्रों और शेष यूक्रेन के बीच एक सशस्त्र सीमा होगी।

दूसरा, यूक्रेन अपनी संप्रभुता बनाए रखे लेकिन, अधिग्रहित क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण खो दे।

तीसरा, युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं हो, लेकिन शत्रुता रुक जाए, जिससे पुनर्निर्माण के प्रयास हो सकें।

चौथा, अमेरिकी सैन्य सहायता में कमी आ जाए, और मॉस्को और कीव के बीच कूटनीतिक चैनल खुल जाएं।

इनका वैश्विक प्रभाव यह होगा कि कोई बड़ा क्षेत्रीय समझौता किए बिना ट्रंप सक्रिय लड़ाई समाप्त करने का श्रेय ले सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा खर्च में कमी आएगी, जिससे ट्रंप को घरेलू नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा, और पुतिन नाटो के साथ "फुल स्केल वॉर" से बचते हुए, यूक्रेन पर दबाव बनाए रखेंगे।

इस तरह के परिणाम का विपरीत पक्ष यह होगा कि यूक्रेन विभाजित रहेगा, दीर्घकालिक अस्थिरता बनी रहेगी, रूस जब चाहे संघर्ष को फिर से शुरू कर सकता है, और नाटो हाई अलर्ट पर रहेगा, क्योंकि भविष्य में रूस की आक्रामकता का खतरा बना रहेगा।

हाईकोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

- **सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के इस आदेश को परेशान करने वाला बताया।**

नयी दिल्ली, 20 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल के उस आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत के मामले की जांच उसके (लोकपाल) अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई, सूर्य कांत और अभय एस ओका की पीठ ने रोक लगाते हुए लोकपाल के इस आदेश को बहुत ही परेशान करने वाला बताया और कहा कि वह इस संबंध में कानून बनाएगी, क्योंकि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत ही होती है। पीठ ने शिकायतकर्ता को शिकायत की विषय-वस्तु या न्यायाधीश का नाम उजागर न करने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद इस पर विचार करेगी। उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश और एक अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश से मार्गदर्शन मांगने पर शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान मामला दर्ज कर सुनवाई की।न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने 27 जनवरी 2025 के आपने आदेश में कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हालांकि, भर्ती होने की वजह और समय अभी सामने नहीं आया है। दिसंबर 2024 में सोनिया गांधी 78 साल की हो चुकी हैं।

सूत्रों के मुताबिक उन्हें रूटीन चेकअप के लिए लाया गया था। इससे पहले सितंबर, 2023 में हल्के बुखार के बाद उन्हें सर गंगा राम अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था।

एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी

मुंबई, 20 फरवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। गोरेगांव पुलिस को इस बारे में एक अज्ञात शख्स का ईमेल मिला है, जिसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।मंत्रालय और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का धमकी भरा मेल आया है।पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है।

- **गोरे गाँव पुलिस को अज्ञात व्यक्ति ने ई-मेल भेज कर धमकी दी है।**

इस समय फिलहाल एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर हैं। वे रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक के लिए निकल गए। दिल्ली में आज रेखा गुप्ता ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है।

जौनपुर में एक ही सड़क पर एक के बाद एक दो हादसे, 9 की मौत 40 घायल

दोनों हादसों में क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ अयोध्या जा रही थीं

- **पहला हादसा गुरुवार अल सुबह हुआ, जिसमें सूमो गाड़ी की एक अन्य वाहन से भिडंत हो गई थी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई।**
- **पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य संभाला, पुलिस बचाव कार्य कर भी नहीं पाई थी कि तथी एक और हादसा हो गया और तीर्थ यात्रियों की बस ट्रेलर से टकरा गई।**

जौनपुर, 20 फरवरी। यूपी के जौनपुर जिले में बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। जिले के बदलापुर थानांतर्गत सरोखनपुर गांव के पास दो अलग दुर्घटनाओं में अयोध्या जा रही गाड़ियां दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इसमें9तीर्थयात्रियों की जान चली गई जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डीएम-एसएसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, महाकुंभ स्नान के बाद दो वाहन जौनपुर में सड़क हादसे का शिकार हो गये। इस हादसे में दोनों वाहनों में सवार नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई है।

लगभग 40 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि झारखंड नम्बर की टाटा सूमो श्रद्धालुओं को लेकर वाराणसी से अयोध्या की ओर जा रही थी। गुरूवार तड़के जैसे ही सरोखनपुर पहुंची तो एक वाहन से जोरदार भिड़ंत हो गई। सूमो में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा। सूमो में एक बच्चा, एक पुरुष और 3 महिला समेत 8 लोग सवार थे। इनमें से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। सूमो सवार सभी झारखंड के रहने वाले थे।

सूमो के हादसे का बचाव कार्य करने के बाद अभी प्रशासनिक टीम सामान्य हो भी नहीं पाई थी कि लगभग आधे घंटे बाद घटनास्थल से सौ मीटर दूर श्रद्धालुओं से भरी बस हाइवे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से भिड़ गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में 42 लोग सवार थे।

इनमें से दो पुरुष और दो महिलाओं की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए। इनमें से 21 लोगों को गंभीर चोटे आई हैं। शेष 11 लोग मामूली घायल हैं। बस सवार दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पक्ष बताने के लिए एक दिन का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती रद्द करने के संबंध में 4 महीने में निर्णय कर लिया जाएगा। इस दौरान किसी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से याचिका को निस्तारित करने की गुहार की। इस पर अदालत ने कहा कि वे दो-तीन माह का समय ले लें, लेकिन याचिका निस्तारित नहीं की जाएगी और इसे मेरिट पर ही तय किया जाएगा।

इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने भी अदालत से कहा कि राज्य सरकार को आगे समय नहीं दिया जाए और याचिका का निस्तारण अभी मेरिट पर कर दिया जाए। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे भर्ती को लेकर तीन साल तक तो कोर्ट आए नहीं, अब उन्हें किस बात की जल्दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए मामले की सुनवाई 20 मिनट के लिए टाल दी। वहीं बाद में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि उनका सक्षम अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। गौरतलब है कि गत सुनवाई पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को मामले में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श होने की जानकारी देकर मामले की सुनवाई बुधवार के बजाए गुरुवार को करने की गुहार की थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908